

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,  
उत्तराखण्ड जल संस्थान,  
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग—२

विषय— जनपद देहरादून स्थित महामहिम राष्ट्रपति आशियाना परिसर में निरन्तर जलापूर्ति योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: २०५६ / टी.ए.सी. / २०१७-१८ दिनांक २२ जून, २०१७ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून स्थित महामहिम राष्ट्रपति आशियाना परिसर में निरन्तर जलापूर्ति कार्य हेतु परीक्षणोपरान्त (निर्माण कार्य हेतु ₹ ६८.७१लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, २०१७ के अन्तर्गत ₹ ०.१०लाख) औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ ६८.८१लाख (₹ अड्सठ लाख इक्याशी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में ₹ २७.५२लाख (₹ सताईस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- (i)— स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii)— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक ३१ मार्च, २०१८ तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii)— कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट्स से स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (iv)— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से ग्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (v)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाने जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)— कार्य कराने से पूर्व समस्ते औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (vii)— उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, २०१७ वित्त नियम संग्रह खण्ड-१ (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-०५ भाग-१(लेखा नियम), आय-व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (viii)— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान छ्या-13 लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति 101-शहरी जल पूर्ति-03-नगरीय पेयजल- 01-नगरीय पेयजल/जलोत्सारण जनाओं का निर्माण-35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन मद के नामे डाला जायेगा।

धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवेटन संख्या— H 07132667 दिनांक 27 जुलाई,2017 से आवेटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या—610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा गत दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अंशा० संख्या-273/XXVII(2)/2017, दिनांक जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)  
अपर सचिव

(1) / उन्तीस(2) / 17-2(31 पे0) / 2017, तददिनांक ।

तेलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. बजट अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा-सं

(सहावीर सिंह चौहान)

संयुक्ता सचिव ।

2 स । अ द । 3. 17 अग्र

(3) क्राय किये गये माल, जैसा कि नियम 46 के उपनियम (2) में वर्णित किया गया हो, के सम्बन्ध में उपर्युक्त अनुच्छेदों का लागत अलग-अलग रखे जायें।